

June 28, 2022

Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai 400 051

**NSE Symbol: SALASAR**

Deptt of Corporate Services  
BSE Limited  
Phirozee Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai 400 001

**Scrip Code: 540642**

Dear Sir/Madam,

**Subject: Intimation regarding dispatch and publication of Postal Ballot Notice**

This is to inform you that, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published the Postal Ballot Notice and remote e-voting instructions in the Business Standard Hindi and English edition newspapers on June 28, 2022.

Further, We would like to inform you that the Company has on 27<sup>th</sup> June, 2022 completed dispatched of Postal Ballot Notice to the members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 24<sup>th</sup> June, 2022.

Please find attached the copies of the aforesaid advertisements.

Submitted for your information and records.

**Thanking You,  
Yours faithfully,**

**For Salasar Techno Engineering Limited**

**Rahul Rastogi  
Company Secretary**

CIN No. - L23201DL2001PLC174076



Unit 1- Khasra 265, 281-283, Parsaun-Dasna, Jindal Nagar, Distt. Hapur-201313  
Unit 2- Khasra 1184, 1185, Khera, Pilkhuwa, Tehsil Dhaulana, Distt. Hapur-245304

Unit 3- Khasra 686/6, Khera, Pilkhuwa, Tehsil Dhaulana, Distt. Hapur-245304  
Office- KL-46, Kavi Nagar, Ghaziabad-201002  
Regd. Office- E-20, South Extension 1, New Delhi-110049

+91 8938802180, 7351991000  
+91 120 6546670  
Fax: +91 11 45823834



towers@salasartechno.com  
marketing@salasartechno.com



### सावर्जनिक सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मनसुख रटोक प्रोपर्टी लिमिटेड सेबी पंजीकरण नं. आईएन-डीपी-06-2015, फंडीकृत कार्यालय नं.4126, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 ने सीडीएसएल के डिवाइजरी फाइलिंग के रूप में अपने पंजीकरण त्याग करने के लिए आवेदन दाखिल किया है। कंपनी ने सीडीआई 16400/02/03/04 के अंतर्गत अपने कार्य परिवर्तन मनसुख रटोक प्रोपर्टी लिमिटेड एवं फाइनेंस लिमिटेड सेबी पंजीकरण नं. आईएन-डीपी-72-2015, फंडीकृत कार्यालय नं.4126, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 को पहले ही सुपूर्द कर दिया है।

कृते मनसुख रटोक प्रोपर्टी लिमिटेड

### SALASAR Building a stronger future

## सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड

CIN: L23201DL2001PLC174076

पंजी. कार्यालय: ई-20, पार्थिव एक्सप्रेसन नई दिल्ली-110049  
Ph: +91-120-6548670, E-mail id: towers@salasartechno.com  
Website: www.salasartechno.com

पोस्टल बैलेट व रिपोर्ट ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा कंपनी (प्रधान व प्रशासनिक) निगमावली, 2014 (इस समय योजुद के लिए किसी वैधानिक संशोधन(बी) या पुनःसंरचना(ओ) के अंतर्गत) के नियम 22 के साथ प्रत्येक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 व अन्य लागू प्राधान्यों और निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र नं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और साधारण परिपत्र नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और साधारण परिपत्र नं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, साधारण परिपत्र नं. 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020 और साधारण परिपत्र नं. 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020 और साधारण परिपत्र नं. 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 ('एसीए परिपत्र') तक उपरोक्त वर्णित परिपत्रों में दिए गए बांधे के विस्तार के संबंध में व सेबी (सूचीबद्ध देयताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम 44 के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोट ('ई-वोटिंग' / रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से वोटिंग द्वारा सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट सूचना निम्नलिखित व्यापार के संबंध में शेषवर्षाओं की अनुमति प्राप्त करने के लिए कट-ऑफ डेट अर्थात् 24 जून, 2022 तक सदस्यों/डिवाइजरी के रिकॉर्ड को ई-मेल द्वारा भेजी जा चुकी है।

क्र. सं.	विषय प्रस्ताव	कंपनी द्वारा फंड लेने और प्रतिभूति या जारी करने की अनुमति देना।
1	साधारण प्रस्ताव : कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी करने और परिणामस्वरूप कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड में राशोधन	
2	विशेष प्रस्ताव : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत रूप रण राशि पर विचार करने व अनुमोदन के लिए	

वोटिंग अधिकार कट-ऑफ डेट तक सदस्यों(बी) में रजिस्टर शेयरों की चुकता मूल्य पर निर्भर किया जाएगा और तिथि तक जो व्यक्ति सदस्य नहीं है, व कंपनी इसे सूचना के उद्देश्य से देखें। आवश्यकता अनुसार, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने के लिए उचित साधन करने के लिए एसी सदस्यों को विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा देने के लिए एनजीसी के रूप में संशुद्ध डिवाइजरी सविधान (इडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') को शामिल की है। ई-वोटिंग द्वारा पोस्टल बैलेट पर वोट डालने की सुविधा निम्नलिखित अधि के लिए उपलब्ध होगी:

ई-वोटिंग की शुरुआत	मंगलवार, 28 जून 2022, सुबह 9.00 बजे से भागसार
ई-वोटिंग की समाप्ति	बुधवार 27 जुलाई 2022, शाम 5.00 बजे से भागसार तक

इस अधि के तहत, कट-ऑफ तिथि अर्थात् 24 जून, 2022 तक पंजीकृत या मेमोरेडम के रूप में इतिवृत्त शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। सदस्यों से व्याख्यात्मक चिपकरण के साथ परिपत्र प्रस्ताव को समझने और निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने और बुधवार, 27 जुलाई, 2022 को शाम 5.00 बजे तक, उसके बाद नहीं ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट डालने का अनुरोध है। बुधवार, 27 जुलाई, 2022 को शाम 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग मॉड्यूल इसके बाद सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। कंपनी के निदेशक नजूल निगम व भावदारी तरीके से पोस्टल बैलेट व ई-वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने के लिए जानकारी के रूप में सीडीएसएल एवं एसोसिएशन (एसीएस) नं. 31234 सी.पी. नं. 14808), अभ्यारसत कंपनी राशि को नियुक्त किया है। एसीएस ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने पर विचार करने के बाद कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। वोटिंग के परिणाम शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 तक या पहले घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज को संचारित किए जाएंगे। जानकारी की रिपोर्ट के सहित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.salasartechno.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर रखे जाएंगे। उचित परिणाम कंपनी को सूचना जांच पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

वोटिंग के लिए निर्देशों के सहित पोस्टल बैलेट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.salasartechno.com और स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com की वेबसाइट के संबंधित नोडेशन में भी उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में रक्षक करने के लिए कंपनी ने उचित वर्णित परिपत्र के संबंध में ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए अपने रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ उचित प्रबंध कर सकते हैं। इस पोस्टल बैलेट के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, अपने ई-मेल पते रजिस्ट्रार व करने वाले शेषवर्षाक कंपनी और कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ रजिस्ट्रार अपने मेल-आईडी अस्थाधी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। शेयरधारक compliance@salasartechno.com और mukesh@bighshareonline.com को अनुरोध लिख सकते हैं। ई-मेल के सहित रजिस्ट्रार के बाद, शेषवर्षाक सूचना और इस पोस्टल बैलेट के लिए ई-वोटिंग में रक्षक करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ सीडीएसएल के ई-वोटिंग की साइट को भी प्राप्त करेंगे। आवश्यकता के लिए प्रक्रिया के लिए निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, अपने ई-मेल पते रजिस्ट्रार व करने वाले शेषवर्षाक कंपनी को सूचना जांच पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

ई-वोटिंग (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्रम संख्या)	यूजर आईडी	किफायत पैर/क्रम संख्या
22062401		अपना पैर उपयोग करें

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू होने की तिथि व समय: बुधवार 27 जुलाई 2022 शाम 5.00 बजे भागसार

अपने रजिस्ट्रार ई-मेल पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, अपने डिवाइजरी को इससे बारे में बताएं। किसी भी पूछताछ के मामले में आप www.evotingindia.com से संपर्क कर सकते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं के लिए यूजर मैनुअल का सफल ले सकते हैं या सीडीएसएल से निम्नलिखित टोल फ्री नंबर 18002005533 या 022-22728153 पर संपर्क करें या कंपनी से संपर्क करें।

सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए हस्ता./- (प्राथमिकता) कंपनी राशि

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 27.06.2022

### आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कर्पोरल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

पंजीकृत कार्यालय: कंसाल्टिंग टॉवर, 8वीं तल, हरिद्वार रोड, चैण्डे, केन्द-600031 फोन: +91 44 4564 4000 | फैक्स: +91 44 4564 4022

#### परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कर्पोरल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधोहस्ताधारी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित 20.04.2021 जारी की थी जिसमें कर्जदार, सह-कर्जदारों और जमानतियों 1. श्री विवेक कुमार शर्मा, 2. श्रीमती आशा रानी, 3. श्री राविन्द्र कुमार शर्मा को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। कर्जदारों द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और जन सामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताधारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का 30 मई, 2022 को नौकिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और सर्वे जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए अज्ञात किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन राशि रु. 7,71,628.93/- (रुपये सात लाख इकहतर हजार छह सौ अठारस और चिरानवे पैंसा मात्र) को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। कर्जदारों द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और जन सामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताधारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का 30 मई, 2022 को नौकिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और सर्वे जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए अज्ञात किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन राशि रु. 7,71,628.93/- (रुपये सात लाख इकहतर हजार छह सौ अठारस और चिरानवे पैंसा मात्र) को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। प्रत्येक परिपत्रितियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्राधान्यों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

नॉव निराकृत की राजस्व संपदा, गोपाल नगर की आबादी, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 स्थित संपत्ति नं. 43, माप 80 वर्ग गज, खसरा नं. 9/2 में से, के समी मांग व खंड और सीमाएं निम्नवत्: पूर्व: रोड 20' चौड़ा, पश्चिम: अन्य जमीन, उत्तर: प्लॉट नं. 43-ए, दक्षिण: अन्य प्लॉट।

दिनांक: 30.06.2022 स्थान: दिल्ली क्रम खाता नं.: 13429821

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कर्पोरल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

### आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कर्पोरल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

पंजीकृत कार्यालय: कंसाल्टिंग टॉवर, 8वीं तल, हरिद्वार रोड, चैण्डे, केन्द-600031 फोन: +91 44 4564 4000 | फैक्स: +91 44 4564 4022

#### परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कर्पोरल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधोहस्ताधारी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित 08.03.2022 जारी की थी जिसमें कर्जदार, सह-कर्जदारों और जमानतियों 1. राजीव कुमार, 2. मंजू रानी से सूचना में उल्लिखित दिनांक 02.03.2022 को राशि रु. 10,34,410.89/- (रुपये दस लाख चौतीस हजार चार सौ दस और उन्हत्तर पैंसा मात्र) को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। कर्जदारों द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और जन सामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताधारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का 23 जून, 2022 को नौकिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और सर्वे जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए अज्ञात किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन राशि रु. 10,34,410.89/- (रुपये दस लाख चौतीस हजार चार सौ दस और उन्हत्तर पैंसा मात्र) को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। प्रत्येक परिपत्रितियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्राधान्यों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

प्लॉट नं. 123 (ख व प्लॉट नं. 2209 नाम से ज्ञात), माप 75 वर्ग गज, खसरा नं. 19/6/2, 15/1, मौजा गाउडी, पूर्ववर्ती कालोनी, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद के समी मांग व खंड और सीमाएं निम्नवत्: पूर्व: प्लॉट नं. 122, पश्चिम: इसी प्लॉट का मांग, उत्तर: दीनार संपत्ति, दक्षिण: रास्ता 15 फुट।

दिनांक: 23.06.2022 स्थान: फरीदाबाद क्रम खाता नं.: 18137285

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कर्पोरल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

### आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कर्पोरल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

पंजीकृत कार्यालय: कंसाल्टिंग टॉवर, 8वीं तल, हरिद्वार रोड, चैण्डे, केन्द-600031 फोन: +91 44 4564 4000 | फैक्स: +91 44 4564 4022

#### परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कर्पोरल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधोहस्ताधारी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित 01.10.2021 जारी की थी जिसमें कर्जदार, सह-कर्जदारों और जमानतियों 1. वीरेंद्र कुमार शर्मा, 2. अजय कुमार, 3. लक्ष्मण सिंह, 4. मंजू देवी, 5. अर के गार्येस्ट प्रॉप. लक्ष्मण सिंह से सूचना में उल्लिखित दिनांक 30.09.2021 को राशि रु. 1,47,33,305.61/- (रुपये एक करोड़ सैतालीस लाख तीस हजार तीन सौ पैंस और इकसठ पैंसा मात्र) को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। कर्जदारों द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और जन सामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताधारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का 24 जून, 2022 को नौकिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और सर्वे जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए अज्ञात किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन राशि रु. 1,47,33,305.61/- (रुपये एक करोड़ सैतालीस लाख तीस हजार तीन सौ पैंस और इकसठ पैंसा मात्र) को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। प्रत्येक परिपत्रितियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्राधान्यों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

टी.डी.एस. सिटी (ट्रंस दिल्ली सिनेमैट सिटी), इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-ए-1, परगना और तहसील- लोनी, जिला- गजियाबाद स्थित संपत्ति प्लॉट नं. एफ-13, एरिया माप 450 वर्ग मीटर, के समी मांग व खंड और सीमाएं निम्नवत्: पूर्व: प्लॉट नं. एफ-14, पश्चिम: प्लॉट नं. एफ-12, उत्तर: रोड, दक्षिण: प्लॉट नं. एफ-15

दिनांक: 24.06.2022 स्थान: गजियाबाद क्रम खाता नं.: 27797691 और 34102328

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कर्पोरल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

### कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताधारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे मंजूदा सूचना में वर्णित शक्ति का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों/गों को भुगतान के लिए एक मांग सूचना जारी की थी।

LAN No.	श्रेणी/वॉ	राशि	मांग सूचना तिथि	13(4) नियम व तिथि	संपत्ति का
LNAWR0031-8-190000547	श्री सुबे सिंह श्री नरेंद्र कुमार व श्रीमती मुंतेरी	₹ 7,42,863/-	21.04.2022	24.06.2022	खसरा नं. 282, गांव घाघौली, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान-301001

श्रेणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा श्रेणी और सदस्यधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताधारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उचित प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर सार्वजनिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से श्रेणी और सदस्यधारण को एतद्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन यहां नीचे वर्णित राशि और उसपर ब्याज सहित आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

स्थान: अलवर दिनांक: 27.06.2022

आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लि. प्राधिकृत अधिकारी

### श्रीराम सिटी यूनिवर्स फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय नं. 123, अन्नगंगा नडकेन स्ट्रीट, वेन्द-600 001. शाखा कार्यालय: 245-246, दूसरी मॉडल, आमकन टॉवर, हुनगम नगर, अमरपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021, वेबसाइट: www.shriramcity.in

## मांग सूचना

जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने श्रीराम सिटी यूनिवर्स फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजूद, कर्जदारों/जमानतियों ने निवृत्त तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विविन नुक को है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-परफॉर्मिग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम सिटी यूनिवर्स फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्यर्थों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं। उनके अंतिम ज्ञाप पते पर सूचनाएं भेजी गयीं और उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सूचित किया जा रहा है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिपेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 को उपधारा (4) के प्राधान्यों को और आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार (रैं) /सह-कर्जदार (रैं) का नाम	बकाया राशि	रूप खान संख्या तथा क्रम रण	प्रतिभूत अस्तियों का सम्पत्ति पता
मेसर्स एस.के. टायर्स (प्रोपाइटर श्री मोहम्मद आजाद श्रेष्ठ)	₹. 10452137/- (रुपये एक करोड़ चार लाख बावन हजार एक सौ सैंतीस मात्र) फोर क्लोजर राशि दिनांक 18.06.2022 के अनुसार	रूप खान CDUDXL P2107 160001 अनुबंध तक्र. ₹. 95,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र)	वाणिज्यिक सम्पत्ति : भूमि/प्लॉट का ससप्त भाग, प्लॉट सं. 02-ए (प्लॉट नं. 02 का भाग, ब्लॉक-डी), ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर, जिला उदयपुर (राजस्थान) में स्थित, माप 833 वर्ग फीट। सीमा विवरण : पूर्व : प्लॉट नं. 02-डी पश्चिम : सड़क उत्तर : प्लॉट नं. 02-बी दक्षिण : प्लॉट नं. 02-बी

मांग सूचना की तिथि : 20.06.2022

उपरोक्त परिपत्रितियों में, एतद्वारा उल्लिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अंतर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं को प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूत आस्तियों के निरुद्ध कार्यावाही की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार को पूर्व सहमति के बिना इस सूचना में समाहित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को परदे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकते।

स्थान: उदयपुर दिनांक: 28.06.2022 श्रीराम सिटी यूनिवर्स फाइनेंस लिमिटेड

## जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

(एक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक)

### ई-नीलामी सूचना

वित्तीय परिसंपत्तिया के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित परंतुक के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

अधोहस्ताधारी ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से उपरोक्त और एक पाने पर जनता को सार्वजनिक सूचित कर रहे हैं कि वे इस संपत्ति के लिए निम्न उल्लेखित कार्यों में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी ('ई-नीलामी') यहां निम्नलिखित दिनांक को 'जो है जैसी है आधार' और 'जो है जैसा है आधार' पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	क्रम खाता सं.	वास्तविक उपाकर्ता/सह-उपाकर्ता/गारंटर का नाम	13-2 सूचना की दिनांक	बांधे की दिनांक	दिनांक 24.06.2022 को वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक और समय	आरंभिक मूल्य रुपये में	अंशिय राशि जमा (रुपये) रुपये में	ई-नीलामी की दिनांक और समय	बोली जमा करने की अंतिम दिनांक, समय और स्थान
1	30218850001931	1) मेसर्स सीडीएस एल अर्धन मासिक श्री सीडीएस एल प्रतिनिधित्व में 2) श्री सीडीएस एल, 3) श्रीमती साधना कुमारी माहलो (गारंटर)	31.07.2019	32.11.2021	रुपये 16,37,494/- (रुपये सोलह लाख तीस हजार चार सौ चौरानवे मात्र)	07.07.2022 सुबह 09.00 बजे से अर्धाह्न 05.30 बजे	10,74,600/- (रुपये दस लाख सात हजार छह सौ मात्र)	1,07,460/- (रुपये एक लाख सात हजार चार सौ मात्र)	13.07.2022 (सुबह 11:00 बजे)	जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय: 16/12, हुसैन टावर, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005
2	30218850004199	1) मेसर्स पारस वेस्ट पेपर अर्धन मासिक श्री पारस कुमार प्रतिनिधित्व में 2) श्री पारस कुमार 3) श्रीमती रंजू देवी (गारंटर)	26.04.2019	17.01.2021	रुपये 6,07,151/- (रुपये छह लाख सात हजार एक सौ इकसठ मात्र)	07.07.2022 सुबह 09.00 बजे से अर्धाह्न 05.30 बजे	6,19,650/- (रुपये छह लाख उन्नीस हजार छह सौ मात्र)	61,965/- (रुपये इकसठ सौ मात्र)	13.07.2022 (सुबह 11:00 बजे)	जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय: 16/12, हुसैन टावर, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

संपत्ति विवरण/अनुसूची: खसरा नं. 484, मापक 200 वर्ग मज खसरा सं. 181 मिन्, निम्न आवासीय कॉलोनी सिम्बर, सिटी, राम लोनी, तहसील लोनी, गजियाबाद, श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री देविचर कुमार शर्मा के स्वामित्व की। सीमांकन प्रकार: पूर्व: अन्य की संपत्ति, पश्चिम: अन्य की संपत्ति, उत्तर: 5 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: अन्य की संपत्ति।

संपत्तियों को 'जो है जैसा है आधार' और 'जो है जैसी है आधार' पर और ई-नीलामी 'ऑन लाइन' आयोजित किया जा रहा है। यह नीलामी बैंक की अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाइपर) के माध्यम से वेब पोर्टल <https://janbank.auctiontiger.net> पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए और विवरण, मापक, प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तर के लिए, संचालित बोलीदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं: संपर्क नंबर: 09722778828/079-681368540/51, 56 ई-मेल आईडी: [praveen.thevar@auctiontiger.net](mailto:praveen.thevar@auctiontiger.net)

ई-नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों श्री शकेस शर्मा (मोबाइल नंबर 7230070463) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी के ज्ञान और जानकारी के लिए, संपत्तियों को पहले संपत्ति के शीर्षक के बारे में हलाकित संशुद्ध बोलौतावली को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी निवेदन जांच करनी चाहिए। प्रत्येक संपत्ति की स्वीकारा नहीं की जाएगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निष्पत्ति ई-नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित उपाकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को सूचनाओं/उपाकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को एतद्वारा नीलामी की दिनांक से पहले अप्राप्त ब्याज और सहस्रक व्यय के साथ उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए आवश्यक किया जाता है, ऐसा न होने पर संपत्ति बेची जाएगी और बकाया राशि को बंद कर दिया जाएगा, ब्याज और लागत के साथ सरल किया जाएगा, यदि कोई हो।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, प्रति. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

दिनांक: 28.06.2022, स्थान: दिल्ली एनसीआर

### फुलरटोन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

फुलरटोन कार्यालय: पानीपत रोड, पानीपत, हरियाणा-150001, फोन: 0182-2222222, वेबसाइट: [www.fulcrumindia.com](http://www.fulcrumindia.com)

## अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(1)

चूंकि, फुलरटोन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (निम्नलिखित हाउसिंग फाइनेंस कंपनी) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंत

# GM crops: One step forward, two steps back

Two decades after Bt cotton made its debut in India, commercialisation of genetically modified crops remains mired in complex procedural issues

SANJEEB MUKHERJEE  
New Delhi, 27 June

Last month, after a considerable gap, the Haryana government gave Mahyco a no-objection certificate (NOC) to seed major field trials of a herbicide-tolerant (HT) and insect-resistant BT cotton variety, called BG-3 RRF. In a normal world, field trials of a new variant would have been a routine exercise that seed companies need to conduct to test a variant before its commercial release or further evaluation.

But given the complexities, delays and political controversy that have marked the commercialisation of genetically modified (GM) crops in India, this relatively small move is being seen as a significant step forward in some quarters.

Seed industry players said the latest application for BG-3 RRF field trials was first submitted in 2016 to the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), but was subsequently withdrawn because things weren't moving forward.

Mahyco re-submitted its application in December 2021, after which the company, according to current procedures, had to get an NOC from each state where it wanted to conduct field trials.

The company approached Haryana for trials to be conducted in Karnal 2022. Field trial data for Punjab was already available with the authorities (having been conducted before 2016).

"But, it seems, this year too will be wasted because cotton sowing has already started in several places in north India and after this trial, the data will have to be submitted to GEAC, which will take its own time since the committee, according to our information, hasn't met for a long time. This means practically another year lost," Ram Kaundinya, director general of Federation of Seed Industry of India (FSII), told Business Standard.

The seed association and some experts said the approval process has been made this complicated so as to deter companies from developing GM variants, putting the whole science into turmoil. The irony of this, however, is that illegal sales of HTBT cotton have grown.

"Farmers won't wait for the



**STRONG FIBRE**  
India cotton yield since 2002

Years	Area under cotton* (in million hectares)	Area under BT cotton** (in million hectares)	Production (in million bales)	Yield (kg per hectare)
2002-03	8.62	0.029	8.62	191
2010-11	11.12	9.63	33	499
2015-16	12.29	10.68	30	405
2019-20	12.58	11.74	32.26	436

Note: All years have not been included; table indicates only major periods in the journey of BT cotton; cotton marketing year runs from October to September  
\*Source: Directorate of Economics and Statistics, a bale is equal to 110 kg  
\*\*Source: DACIAT, state governments and Directorate of Cotton Development, Nagpur

official release of new Bt cotton variants, which is why around 20 per cent of the total cotton acreage in the country is under illegally grown HTBT cotton," Kaundinya said.

For seed companies, the trouble started back in 2010, when the then government, while putting a moratorium on further trials of Bt brinjal, had issued two other notifications.

One was to change the nomenclature of GEAC from Genetic Engineering Approval Committee to Genetic Engineering Appraisal Committee. The second was to make it mandatory for all applicants to get NOCs from each state in which they want to conduct field trials of GM crop variants cleared by the GEAC.

The first change, pro-GM scientists said, made political interference in the final approval of GM crops more pronounced. The second pushed the entire burden of GM approvals to the states, which do not have the expertise to handle such complicated and technical issues as GM technology.

As a result, the entire structure of GM approvals and trials was stalled. Though some progressive states did approve field trials, those were few and far between. Subsequently, with little forward movement, several companies withdrew their applications for field trials. Thereafter, in 2017, the entire clearance process underwent another change.

Pro-GM groups said that the government, through an informal directive, said that unlike the earlier system of GEAC clearance being subject to NOCs from state governments, the new system required companies and institutes to first get an NOC for field trials from states before seeking GEAC approval.

"This overturned the entire process and states, being ill-equipped to handle issues related to field trials of GM crops in the first place, particularly when the GEAC had not cleared them, stopped giving NOCs altogether. As a result, for the past five or six years, no field

trial of any GM crop has taken place in the country," said Bhagirath Choudhary, founder director of the South Asia Biotechnology Centre.

He said the entire process has been made so complicated and slow that companies fear venturing into this. "That is why in the last 33 years, just one crop (cotton) has been approved for commercial usage," Choudhary said.

Meanwhile, demand from farmers is growing as attacks of pink bollworm, one of the biggest pest infestations facing cotton farmers in India, are rising by the day.

The result, Choudhary pointed out, is that cheap fakes of BG-3 are proliferating the market, causing losses to all.

He said a strong regulatory mechanism proposed under the draft Biotechnology Regulatory Authority of India Bill should be again considered to ensure that science does not suffer. But the bill has been in cold storage since 2008.

On the other hand, G V Ramanjaneyulu, executive director, Centre for Sustainable Agriculture, feels that unless there is a regulatory system that caters to the requirements of 21st-century India, curtailing field trials is the only way to ensure that biosafety protocols and norms as far as GM crops are concerned are not violated with impunity by seed companies.

"Also, one must remember that the Supreme Court-appointed high-powered committee on GM crops and subsequent parliamentary panels had found that there is no need for HT crops in the country. So, unless there is an intention to bypass the panel's recommendations, states should not allow field trials of GM crops," Ramanjaneyulu said.

The SC panel had said that over time, HT crops would most likely exert a highly adverse impact on sustainable agriculture, rural livelihoods and environment, and that the panel found them completely unsuitable in the Indian context.

Kaundinya of FSII said that as a middle path, the Centre could explore the possibility of notifying some sites within ICAR-Centres or agriculture universities where field trials of GM crops can be conducted.

"We at FSII have asked for NFTS — notified field testing sites — for the last two years to at least move things forward; otherwise, there is no end to the stalemate," he said.

# Manufacturers decry ban on rigid single-use plastics

Industry grouse: no specifications fixed for products, although they are fully recyclable; non-recyclable packaging used by FMCG firms let off

SURAJEET DAS GUPTA  
New Delhi, 27 June

Days before the July 1 ban on 22 single-use plastic products, makers of rigid plastic plates, trays, spoons and forks, belonging mostly to the small-scale sector, have complained to the government of adopting different standards on banning single-use plastics.

The Thermoformers and Allied Industries Association (TAIA), which represents 850 manufacturers employing 200,000 people (and 500,000 indirectly), has pointed out that while the government has imposed a blanket ban on their products without providing any specifications for exemptions, it has exempted multi-layered packaging used by large global and domestic fast-moving consumer goods companies for packing snacks, chips, coffee and so on.

This, despite the fact that these packaging materials, with thickness between 20 and 30 microns, are litter-prone, non-bio-degradable, non-recyclable and are made out of materials such as plastic and aluminium.

What's more, says the TAIA, exemption has also been granted to high-density polyethylene (HDPE) carry bags of above 75 microns (they have to go up to 100 microns by December), which are also single-use plastics,



**LOSING BATTLE**

- The government has banned rigid plastic products without any specifications for exemption, even though these products are 100% recyclable
- The ban threatens to shut down ₹10,000-crore, mostly small-scale, sector
- Multi-layered packaging used by big FMCG companies has been allowed, although it is tough to recycle
- HDPE carry bags with thickness above 75 microns have been exempted from ban
- 200 ml single-use PET bottles also on the exemption list

Even PET (polyethylene terephthalate) bottles with capacity above 200 ml that are commonly used by beverage companies are on the exemption list.

Yet the government has banned the products of the rigid plastic packaging industry, worth ₹10,000 crore, even

though they are recyclable and have thickness above 150-200 microns. (Heavy materials can be picked up and recycled unlike lighter ones that stay on in landfills). The rules prohibit the manufacture, sale, distribution and inventory storage of these products despite the fact that they

account for only 1.5 per cent of all the gross waste from single-use plastics. Says Bhavesh Bhojani, secretary of the TAIA, "What we are asking is that just like in other categories, the government should come out with specifications that we have to follow to get exemption. After all, our products are fully recyclable. And we need some time to adjust to the new specifications."

He says that in its presentation to the government, the TAIA has asked for specifications for exemptions — such as rigid plastic plates and trays not weighing less than 5 gm or having thickness not below 150 microns, and plastic cups and glasses weighing not less than 5 gm or having a capacity of 210 ml.

Bhojani points out that loss of employment apart, loans exceeding ₹5,000 crore taken by the companies will turn into non-performing assets if the ban is imposed.

Experts argue that while multi-layered packaging has been allowed because it provides shelf life, under the new recycling rules 30 per cent of the plastic that goes into them has to be recycled over the next three years. The government has also made producers, brand owners and importers responsible for giving details of the way they are recycling the plastic they use.

## ON SENTIMENTS

# Disparate and slow recovery of sentiments



MAHESH VYAS

After over two years since the devastating lockdown of March-April 2020, the Index of Consumer Sentiments (ICS) is still significantly lower than its pre-lockdown level. The ICS of May 2022 was 35.7 per cent lower than its level in February 2020. Households have suffered a lot more than can be gauged by the usual economic indicators like GDP growth.

The recovery has been uneven. Enterprises reaped record profits and the government benefited by collecting record taxes. But, households struggled to see their nominal incomes recover to their pre-pandemic levels. Average household income in January 2022 was just 3.1 per cent higher in nominal terms than its January 2020 level. The consumer price index rose by 11.4 per cent during the same period. Real household income, therefore, remained much lower than its level before the lockdowns. This is a severe hit to households.

It is not surprising, therefore, that consumer sentiment continues to be seriously bruised.

Household perceptions of their own well-being and expectations of their future continue to be worse than they were before the lockdowns.

Consumer sentiments have been recovering, but at a very slow pace. Worse still, this recovery has been decelerating in recent months. Further, this recovery is skewed in favour of the rich.

Between June 2020, when the recovery began, and May 2022, the average monthly increase in the ICS was 2.2 per cent. The median monthly increase was also 2.2 per cent. In January and February 2022, the growth was distinctly higher at 4 per cent and 5 per cent, respectively. Then it fell to 3.7 per cent in March, 3 per cent in April and 0.8 per cent in May. This is the slowing of the recovery process.

June 2022 might do better, but it is unlikely to reflect any significant improvement in sentiments.

The 30-day moving average ICS as of June 26 was 1.3 per cent higher than its level as of May-end. The last four days of June are unlikely to change this position much. The June 2022 ICS may be about 1.3 per cent higher than the level in May 2022.

This looks like a recovery from the falling growth trend and the abysmally low 0.8 per cent growth recorded in May. But, the trend seen during the four weeks of June does not reinforce such a belief. Much of the growth of the ICS in June is

derived from the nearly 9 per cent jump recorded in the first week. After that the index fell by 1 per cent in the second week and recovered by 1.3 per cent in the third week. But, in the week ended June 26, the ICS fell by a substantial 2.1 per cent. This weekly growth does not support the recovery argument.

Household expectations for the future are muted. This is, perhaps, understandable. Job prospects are not getting any better for the vast majority. The recent Agniveers episode was bad optics for young hopefuls. Inflation has been high and interest rates have been rising. The southwest monsoon got off to a patchy start and kharif sowing is delayed. None of this bode well for households that have still not recovered, in real terms, from the lockdown blow.

While the ICS as of June 26 was 1.3 per cent higher than its level in May 2022, the Index of Current Economic Conditions (ICC), which reflects current conditions of households, had done much better, having scaled up by 2.7 per cent. Growth in the Index of Consumer Expectations (ICE), which reflects expectations, was muted. It grew by only 0.4 per cent.

Poorer households have seen a much slower recovery in consumer sentiments compared to the well-off households. While the overall ICS in May 2022 was 35.7 per cent lower than its pre-pandemic level in February 2020, the ICS of households with

incomes less than ₹100,000 per annum was 46 per cent lower.

The pace of recovery of the ICS was directly proportional to the income levels of households. The ICS of households with an annual income between ₹100,000 and ₹200,000 was 40.4 per cent lower; those with incomes between ₹200,000 and ₹500,000 per annum saw the ICS fall by a lower 31.2 per cent; and those with incomes between ₹500,000 and ₹1 million per annum saw the ICS fall by an even lower 30.7 per cent. The lowest fall in the ICS is of households with the highest income bracket of more than ₹1 million per annum. The ICS of these households in May 2022 was 25.2 per cent lower than in February 2020.

This income disparity in consumer sentiments got sharper in May 2022. The overall ICS had grown by 0.8 per cent in the month. However, the lowest rung saw sentiments decline by a substantial 8.2 per cent and the next rung saw their ICS shrink by 3.2 per cent. Only households that earned more than ₹200,000 per annum recorded an increase in ICS in May. The ICS of households with an annual income between ₹200,000 and ₹500,000 increased by 2.4 per cent.

Richer households reported much higher growth in ICS in May 2022. Those with incomes between ₹500,000 and ₹1 million per annum saw their ICS jump up by 18 per cent, and those with annual income in excess of ₹1 million saw their ICS go up by 19.4 per cent.

The slowing down of consumer sentiments can delay the recovery in private final consumption expenditure and the disparity in its recovery has implications on the nature of the recovery.

The writer is MD & CEO, CMIE Pvt Ltd

**AMRIT HATCHERIES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)**  
Regd Office: 158, Lenin Sarani, 3rd Floor, Kolkata-700013, West Bengal  
Liqudator's Address: Sumedha Management Solutions Pvt. Ltd., 8B Middleton Street, 6A Geetanjali, Kolkata - 700 071, India  
Contact: 7980129754 ; E-mail: ip.amrithatcheriespvtltd@gmail.com

E-Auction Sale Notice for Sale of Assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with Regulation 33(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016. Notice is hereby given to the Public in general that the below described assets of Amrit Hatcheries Private Limited will be transferred as "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" "WHAT EVER THERE IS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS" and as such on date as mentioned in the table herein below under liquidation. The Reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal www.eauctions.co.in on 14.07.2022. The general public is invited to bid either personally or by duly authorized agent.

SCHEDULE OF ASSETS	(in Crores)			
Lot No.	Description of Assets	Reserve Price	EMD	Incremental Amount
1.	Building & Structures, Plant and Machinery & Vehicles located at mouza-raghuinathpur, p.s.-Kanksha under bankhati gram panchayat, district-paschim bardhaman, West Bengal-713144.	11.25	1.12	0.10
2.	3 Vehicles (WB 67 A 5484, WB 67 A 2844 and WB 67 A 8056) and 1 Bike located at Village-Kashibedia, P.O-Bora Chingra, Bankura, West Bengal, Pincode-722144	0.10	0.1	0.1
3.	Assignment of book debts and advances	0.06	0.005	0.01

Last date of EMD Deposit: 13.07.2022/Last Date/TIME of bidding: 14.07.2022, 13.00 hrs.

The sale shall be subject to the terms and conditions prescribed in the Process Documents and to the following conditions:

- The particulars of the assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best information of the liquidator, but the liquidator shall not be answerable for any error, misstatement, or omission in this proclamation.
- It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The inspection of assets put on auction will be permitted to interested bidders at sites from the date of publication to the last date of submitting documents & EMD. The liquidator shall not be responsible for any charge, lien, encumbrance, or any other dues to the Government or anyone else in respect of the assets-auctioned. The intending bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc.
- The interested bidders shall deposit the EMD by way of Demand Draft favouring "Amrit Hatcheries Private Limited (in liquidation)" or through bank transfer by the last date as mentioned in the above noted table, to the following account-Amrit Hatcheries Private Limited (in liquidation) Account No. 008900210122454, IFSC Code: PUNB0008900. The draft should not be of a Co-operative Bank.
- The bidders are requested to visit www.eauctions.co.in for detailed terms and conditions for e-auction process before submitting their bids and taking part in the e-auction sale proceedings.

Communication Address: Sumedha Management Solutions Pvt. Ltd., 8B Middleton Street, 6A Geetanjali, Kolkata - 700 071, India  
Contact: 7980129754 ; E-mail: ip.amrithatcheriespvtltd@gmail.com

Bijay Murnuria  
Liqudator, M/s. Amrit Hatcheries Private Limited  
Place: Kolkata  
Date: 28.06.2022  
IBBI Reg. No. : IBBI/PA-001/PA-N00007/2016-2017/10026

**SALASAR**  
Building a stronger future

**SALASAR TECHNO ENGINEERING LIMITED**  
CIN: L23201DL2001PLC174076  
Regd Office: E-20, South Extension 1, New Delhi-110049  
Ph: +91-120-6546670; E-mail id: tovers@salasartechno.com  
Website: www.salasartechno.com

**NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING**

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and in terms of the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, the General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 and the General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No.10/2021 dated June 23, 2021 in relation to extension of the framework provided in the aforementioned circulars up to December 31, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Postal Ballot notice seeking consent of the Members by voting through electronic mode ("e-voting/franchise voting"), has been sent by e-mail to the members/Record of Depositories as on the Cut-off date i.e. June 24, 2022 for obtaining the approval of the Shareholders' in respect of the following business.

Item No.	Description
1.	Special Resolution: To approve raising of funds and issuance of securities by the Company
2.	Ordinary Resolution: To increase in authorized share capital of the company and consequent alteration in capital clause of the Memorandum of Association of the company
3.	Special Resolution: To consider and approve borrow money U/s 180(1)(c) of the Companies Act, 2013

Voting Rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member(s) as on the Cut-off date and any person who is not a member as on date should treat the Postal Ballot Notice for Information Purposes only. As required, the Company is pleased to offer E-voting facility as an option to all the Members, to enable them to cast their votes electronically. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the agency to provide e-voting facility. The facility to exercise vote on postal ballot by e-voting, will be available for the following period:

Commencement of e-Voting	From 09:00 a.m. IST on Tuesday, June 28, 2022
End of e-Voting	Upto 05:00 p.m. IST on Wednesday, July 27, 2022

During this period members of the Company holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. June 24, 2022 may cast their vote electronically. The members are requested to peruse the proposed resolution along with the explanatory statement and carefully read the instructions and cast a vote through e-voting facility not later than on Wednesday, July 27, 2022 at 5:00 P.M. (IST). E-voting shall not be allowed after 5:00 P.M. on Wednesday, July 27, 2022. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Board of Directors of the Company has appointed Deepika Madhwal & Associates (ACS No. 31234, C.P. No. 14808), Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report to the Chairman & Managing Director of the Company or any other person authorized by him, after taking into consideration votes cast through e-voting. Based on Scrutinizer's Report, the result of the voting will be announced on or before Friday, July 29, 2022 and will be communicated to the stock exchanges. The result along with Scrutinizer's Report will be placed on the website of the Company at [www.salasartechno.com](http://www.salasartechno.com) and on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). The said results shall also be displayed on the Notice Board of the Company.

The Notice of Postal Ballot alongwith the instructions for voting is also available on the Company's website at [www.salasartechno.com](http://www.salasartechno.com) and at the relevant sections of the websites of the stock exchanges on which the shares of the Company are listed i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). To enable participation in the remote e-voting process the Company has made appropriate arrangement with its Registrar & Share Transfer Agent for registration of email addresses in terms of the above-mentioned Circular. Pursuant to the aforesaid Circular issued by Ministry of Corporate Affairs, for remote e-voting for this Postal Ballot, shareholders who have not registered their email address may temporarily get their email address registered with the Company & Company's Registrar & Share Transfer Agent. Shareholders may write the request to [compliance@salasartechno.com](mailto:compliance@salasartechno.com) and [mukesh@bigshareonline.com](mailto:mukesh@bigshareonline.com). Post successful registration of the email, the shareholder would get copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for this Postal Ballot. You are requested to avail the remote e-voting facility by logging on to CDSL's e-voting system [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). The Password and User ID for e-voting are as under:

EVSN (Electronic Voting Sequence Number)	USERID	Default PAN / Sequence Number
220624001		USE YOUR PAN

Electronic Voting Start Date and Time	Electronic Voting End Date and Time
Tuesday, June 28, 2022 09:00 a.m. IST	Wednesday, July 27, 2022 05:00 p.m. IST

In case there is any change in your registered email address, kindly update the same with your Depository. In case of any queries, you may refer to the user manual for shareholders available at the help sections of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or contact CDSL at the following toll free telephone number: 18002005533 or 022-27781513 or contact the Company.

For Salasar Techno Engineering Limited  
Sd/-  
(Rahul Rastogi)  
Company Secretary

Place: New Delhi  
Date: 27.06.2022

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL**  
**BENCH, AT CHENNAI**  
CP/ISS/CA/2022  
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013  
And  
In the matter of sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013  
And  
In the matter of Scheme of Arrangement (Demerger) between  
Frendi Fashions Private Limited and  
Frendi Ventures Private limited and Frendi Enterprises Private Limited and their respective shareholders and creditors.

**Frendi Enterprises Private Limited**  
Having its registered office at, Nikitasha Chamber, No.5/92, Butt Road, St.Thomas Mount, Chennai- 600 016, Represented by Director Mr. Dipak Raj

...Petitioner Demerged Company (2)

**NOTICE**

Notice is hereby given that by an order dated 01<sup>st</sup> day of June 2022, the Chennai Bench of the National Company Law Tribunal has fixed the date of hearing of the Company Petition filed by the Petitioner Company (Frendi Ventures Private Limited) under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for the sanction of Scheme of Arrangement (Demerger) between Frendi Fashions Private Limited and Frendi ventures Private limited and Frendi Enterprises Private Limited and their respective shareholders and creditors, on the 27<sup>th</sup> day of July 2022. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner's Advocates, notice of his intention, signed by him or his Advocate, with his name and address, so as to reach the Petitioner's Advocates not later than two days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

**HARISHANKAR MANI**  
**PAWAN JHABAKH**  
Counsel for the Petitioner

Dated this 28<sup>th</sup> day of June, 2022  
New No. 115, First Floor, Luz Church Road, Mylapore, Chennai – 600004